इसके अतिरिक्त, दो निजी संस्थाओं के संबंध में सिफारिश की गई थीः

(i) बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी

(ii) मणिपाल उच्च्य शिक्षा अकादमी, मणिपाल

इसके अतिरिक्त, ग्रीन फील्ड श्रेणी के अंतर्गत आगामी 3 वर्ष में एक संस्था (जियो संस्थान) स्थापित करने के लिए 'आशय पत्र' जारी करने का प्रस्ताव किया गया था।

Construction of World Class Institutes

†*22.SHRI HARIVANSH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state the names and details of progress made with regard to the construction of ten world class universities announced by the Central Government in the last budget?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

As per the budget announcement 2016 University Grants Commission (UGC) issued/ notified the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public Institutions and UGC (Institution of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 for private Institutions to enable 10 public and 10 private Institutions to emerge as World Class Teaching and Research Institutions called on 'Institutions of Eminence' (IoEs).

In accordance with the regulations, the Empowered Expert Committee (EEC) has been constituted *vide* order dated 20th February, 2018. A notification seeking applications from the eligible institutions has been issued on 13th September, 2017. Accordingly, 114 applications - 74 from public sector and 40 from private sector, including 11 applications in the Greenfield projects have been received.

EEC after thorough examination of applications and presentations made by the institutions has made recommendations.

The EEC report was examined by UGC in its meeting held on 9th July, 2018 and it was resolved that 3 institutions from the public category and 3 from private category may be notified in the first instance. Accordingly, the following public institutions have been approved for notification as Institutions of Eminence (IoEs).

† Original notice of the question was received in Hindi.

(i) Indian Institute of Science, Bangalore

(ii) Indian Institute of Technology, Delhi

(iii) Indian Institute of Technology, Bombay

Further, two private institutions were recommended.

(i) Birla Institute of Technology and Sciences, Pilani

(ii) Manipal Academy of Higher Education, Manipal

Apart from this, one institution (Jio Institute) was proposed under the Greenfield category for issue of 'Letter of Intent' for setting up of an institution in the next 3 years.

श्री हरिवंशः सभापति महोदय, मैं इस संबंध में आपके माध्यम से अपना पहली सप्लीमेंटरी रखने से पहले उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार के इस काम की मैं सराहना करता हूं, पर इस काम के लिए चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, एन. गोपालस्वामी ने कहा कि हमने बड़ी सावधानी से eligibility criteria की जांच की, पर भारत में बीस संस्थान भी ऐसे नहीं मिले, जिन्हें देख कर हमें लगा कि विश्व के 500 विश्व स्तर की संस्थाओं में वे आगामी दस वर्षों में भी अपनी कोई जगह बना पाएंगे। क्या सरकार को हमारी इन शिक्षण संस्थाओं की यह क्वालिटी मालूम है? आज नॉलेज सोसाइटी में हमारे सारे विश्वविद्यालयों में से अगर बीस ऐसे नहीं मिले, जो आगामी दस वर्षों में दुनिया के 500 विश्वविद्यालयों में अपनी जगह पा सकें, तो किस तरह से आगे की योजना है? मैं उसमें एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूं।

श्री सभापतिः आप सेकंड सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं।

श्री प्रकाश जावडेकरः सर, सच्चाई यह है कि हमारे पास 900 विश्वविद्यालय हैं, we have nine hundred universities. But, in the international ranking, in the first two hundred, we have only one. So, that is the real state of affairs, and therefore, that is a serious thing. Therefore, in 2016 Budget, this scheme was announced for Institute of Eminence. There, it is proposed that ten in public sector and ten in private sector universities or institutes will be selected which can then attain that quality with two things. For public institutes, we will give extra funding; for private institutes, we are not giving a single paisa; and second, more importantly, they require freedom so that they grow. यह जो एम्पावर्ड कमेटी थी, उसमें सभी भारतीय ही थे, लेकिन जो दो यहां काम करने वाले और दो, विदेशों के विश्वविद्यालयों के जो वाइस-चांसलर बने हैं, जो कि first hundred में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके भी लोग थे। इस कमेटी ने सबका प्रेजेंटेशन लिया और प्रेजेंटेशन लेकर यह कहा है, लेकिन गोपाल स्वामी जी ने exactly क्या कहा, यह मैंने अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उनकी टिप्पणी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह है कि Institute of Eminence, एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। मैं मानता हूं

कि आज 6 हुए हैं, आगे भी होते जाएंगे, क्योंकि अब हर वर्ष गुणवत्ता सुधार के बहुत भरसक प्रयास हो रहे हैं।

श्री हरिवंशः सभापति महोदय, मैं अपना दूसरा सप्लीमेंटरी सवाल पूछने से पहले एक चीज़ कहना चाहूंगा कि मैं एक तरफ आप जो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उसकी सराहना करता हूं, पर जहां 700 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, उनमें क्या स्थिति है? आज ही एक अखबार में खबर है, लीड खबर है, 'Inside India's fake research paper shops pay, publish and profit.' 700 जनरल्स एक कमरे से निकलते हैं और टॉप एकेडेमिक इंस्टिट्यूशन्स में जनरल्स में लेख छपवा कर वह सीवी अच्छा बना कर अध्यापन का काम करते हैं। अगर यह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन 700 विश्वविद्यालयों में रहे और 10 विश्वविद्यालयों को आप अच्छा बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि भारत को उस स्तर पर लाने के लिए कई सौ वर्ष लगेंगे और आपका जो मकसद है, शायद वह पूरा न हो पाए।

श्री प्रकाश जावडेकरः सर, यह सच नहीं है कि 700 विश्वविद्यालय में फेक डिग्रीज़ मिलती हैं। रिसर्च में कुछ जगहों पर यह तरीका ध्यान में आया, इसलिए हमने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है, जिसके माध्यम से, जो palgiarism होती है, कहीं भी कॉपी करके जो करते हैं, वह तुरंत पकड़ी जाएगी। इस तरह की व्यवस्था अब की गई है। इसको सभी के लिए मेंडेटरी भी किया गया और सभी विश्वविद्यालयों को कहा है कि अनेक प्रकार के साफ्टवेयर उपलब्ध हैं, एक मजबूत सॉफ्टवेयर लेकर उसके माध्यम से हर पीएचडी. thesis की जांच की जाए। इस तरह से अगर वह कॉपी कहीं से ली गई होगी, तो वह चोरी पकड़ी जाएगी। इस तरह की भी व्यवस्था की है। मुझे लगता है कि इससे भी सुधार होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा है, लेकिन यह भी सही नहीं है कि सब कुछ एकदम ठीक है, इसलिए ठीक करने की कोशिश लगातार चलेगी और यह चल रही है।

श्री सभापतिः श्री महेश पोद्दार।

श्री महेश पोद्दारः सभापति जी, यह तो बहुत खुशी की बात है कि हमने वैश्विक विश्वविद्यालय के बारे में सोचना शुरू कर दिया है और इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। इस देश में 'गरीबी हटाओ' से 'अंत्योदय' तक बहुत सारे प्रयास गरीबी हटाने के लिए हुए। कृषि का क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है।

श्री सभापतिः आप इस विषय पर आइए, हम लोग शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

श्री महेश पोद्दारः जी हां, सर। जो यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, वह साइंस, टेक्नोलॉजी और प्रबंधन के विषय जो आम हैं, उन पर तो बनेगी ही, पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चूंकि यह विश्व की समस्या है, इसलिए क्या गरीबी उन्मूलन को फोकस करके क्या कृषि क्षेत्र में तरक्की के लिए वैश्विक स्तर का कोई विश्वविद्यालय खोलने की दिशा में कुछ प्रयास करेंगे?

श्री प्रकाश जावडेकरः माननीय सदस्य जी का यह सुझाव बहुत अच्छा है और महत्वपूर्ण भी है। अभी तक इसमें सभी संस्थाओं, except management को नहीं लिया गया था, लेकिन बाकी सभी संस्थाओं को लिया गया था, लेकिन "फोकस यूनिवर्सिटी", यह इसकी एक कैटेगरी हो सकती है। यह एक विचारणीय सुझाव है।

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, we are discussing as per your directions. The report says that you are trying to promote ten universities as universities of eminence. You have already announced four. In that, there is not even one public university, at all. Besides that, there is one university which does not even exist. What exactly is your answer to that?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, Indian Institute of Science, Bengaluru is there; it is a public institute, IIT Bombay is a public institute, IIT Delhi is a public institute. इसके साथ ही, BITS Pilani, जो एक प्राइवेट इंस्टिट्यूट है, वह सालों से काम कर रहा है और मनिपाल यूनिवर्सिटी भी वर्षों से काम कर रही है, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसा कि आपने कहा, ये दोनों ही प्राइवेट कैटेगरी की हैं और सरकार इनको कोई पैसा नहीं देगी, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी है। जो थोड़ी-सी एक misunderstanding पैदा हुई, वह इसलिए हुई कि इन तीनों के नाम साथ में आए, लेकिन Jio यूनिवर्सिटी, जो कि propsed है, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि एक कैटेगरी ग्रीनफील्ड कैटेगरी थी। ग्रीनफील्ड कैटेगरी में ऐसे 11 प्रपोज़ल्स विश्व के उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आए, जो आज नहीं हैं, लेकिन वे 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ देना चाहते हैं। जयराम रमेश जी और बाकी सभी लोग यह मानेंगे कि विश्व में ऐसे अनेक विश्वविद्यालय तैयार हो गए, जिनके निर्माण में वहां के धनी लोगों ने अपनी पूरी संपत्ति लगा दी और अच्छे-अच्छे विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। अच्छे विश्वविद्यालय तैयार हों, इसके लिए एक ग्रीनफील्ड कैटेगरी थी और उसमें 11 एप्लिकेशंस आए थे। उन सभी का प्रेजेंटेशन लेने के बाद अभी उनको Institute of Eminence का टैग नहीं दिया गया है, बल्कि उनको अभी Letter of Intent दिया गया है। Letter of Intent देने के बाद अब यह देखना है कि तीन साल में वे कैसी तरक्की करते हैं, फिर उसके आधार पर ही उनको Institute of Eminence का टैग मिलेगा।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, institutions become world-class when students are world-class and the faculty is world-class. Indian students are world-class. The problem in Indian institutions is faculty, whether it is IITs or IIMs. The students are world-class. The faculty shortage in Delhi is 40 per cent; faculty shortage in IIT Bombay is 38 per cent. So, I would like to ask the hon. Minister as to how he is going to address the problem of faculty in these public institutions. Students will take care of themselves. But, you have to have an aggressive approach for making the faculty world-class.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I fully agree that our students are really one of the best students in the world and that the real problem is the faculty crunch. Therefore, what we have decided and acted upon is that we have asked all the IITs, institutions, Central Universities, etc., to scout all over the world for good faculty members. Rolling advertisements are there; extending continuous invitations for those who want to come into the teaching profession must be encouraged and they must be taken in. It is a roll-on advertisement programme.

Sir, let me tell you about the second programme. There will be IIT Council Meeting next month. Till now, all IITs went differently to different countries in an effort to recruit the faculty from the Indian diaspora comprising NRIs or CIO. What we are asking them now is to do the common bargaining. इसके लिए सब मिलकर प्रयास करें और इस प्रयास से अच्छी faculty लाएं। यह चैलेंज है, क्योंकि अच्छे technologist तैयार होते हैं, उनको प्राइवेट से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केन्द्र सरकार ने भी सहूलियतें दी हैं। Faculty को हम फ्रीडम भी देंगे, उनको यहां consultancy का फ्रीडम भी मिलेगा और इस Institute of Eminence of graded autonomy में उनको variable pay की सुविधा भी मिलेगी।

श्री सभापतिः क्या आप अच्छी faculty देते समय जयराम जी जैसे लोगों को भी consider करेंगे?

श्री प्रकाश जावडेकरः उनको हमारा permanent invitation है। ...**(व्यवधान)**...

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विघटन

*23. **चौधरी सुखराम सिंह यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है किं मत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को विघटित कर उच्च शिक्षा आयोग गठन करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वह कौन सी विसंगतियां हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिक्षा क्षेत्र में सुधार से रोक रही हैं और जिसे इसके द्वारा दूर नहीं किया जा सकता; और

(घ) नए आयोग के गठन के बाद शिक्षा क्षेत्र में प्रस्तावित परिवर्तन का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम को निरस्त करने और शैक्षणिक अनुदेश की गुणवत्ता बढ़ाने, शैक्षणिक मानकों का अनुरक्षण करने और ज्ञान, नवाचार, ऊष्मायन (इन्क्यूवेशन), कौशलों और उद्यमिता के निःशुल्क अर्जन एवं सभी के लिए पहुंच, समावेशन और अवसरों को असान बनाने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करने तथा उच्चतर शिक्षा का व्यापक व सर्वांगीण विकास और एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक वातावरण में शोध उपलब्ध कराने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना करने हेतु भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2018 का मसौदा तैयार किया है।